

सभी सस्थाओं में 20 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित करना अपेक्षित है। वैज्ञिक सस्थाओं को यह सलाह भी दी जाती है कि किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए अंकों की न्यूनतम अपेक्षित प्रतिशतता में 5 प्रतिशत की रियायत दें और यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए रखे गए 20 प्रतिशत स्थान नहीं भर पाते तो उस विद्या में अंकों में और आगे छूट दी जाए। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने उच्च शिक्षा की सस्थाओं में पिछड़ी जातियों के लिए स्थानों के ऐसे आरक्षण के लिए कोई मार्गदर्शी रूप रेखाएँ नहीं बताई हैं।

(ख) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में पिछड़ी जातियों से संबंधित छात्रों के लिए स्थान आरक्षित किए हैं —

- 1 बम्बई
- 2 भागलपुर
- 3 बंगलौर
- 4 कुवशेत्र
- 5 कश्मीर
- 6 कर्नाटक
- 7 मद्रास
- 8 मैसूर
- 9 मद्रुरई
- 10 मगध
- 11 मराठावाड़ा
- 12 महाराष्ट्र फुले कृषि विद्यापीठ
- 13 मराठावाड़ा कृषि
- 14 पंजाब
- 15 पंजाबी

- 16 पटना
- 17 पूना
- 18 श्री वैकटेश्वर
- 19 सरदार पटेल
- 20 शिवाजी
- 21 कोचीन
- 22 नागपुर

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय खाद्य नियम द्वारा रायपुर जिले में रखे गए गेहूँ का खाने योग्य न रहना

1156 श्री ब्या राम शास्त्र कया कृषि और सिबाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय खाद्य नियम का 13 नख रूपों के मल्य का गेहूँ जो मध्य प्रदेश में रायपुर जिले में खुले में रखा था, मनुष्यों के खाने लायक नहीं रहा, और

(ख) यदि हा, तो सरकार ने भारतीय खाद्य नियम के सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने लापरवाही दिखाई, क्या कार्रवाही की है ?

कृषि और सिबाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) (क) जी नहीं। यह क्षति खाद्यान्नों को डिपो लाने समय मार्ग में हुई थी जब तकानी मौसम के फलस्वरूप 211 बूँदें बैंगनों पर डाली गयीं तिरपालों के हट जाने के कारण खाद्यान्न ला रहे बोरे वर्षा से भीग गये थे।

(ख) प्रश्न ही ही नहीं उठता। क्योंकि यह क्षति भारतीय खाद्य नियम के अधिकाधिकारियों की किसी लापरवाही के कारण नहीं हुई थी बल्कि मार्ग में अपरिहार्य कारणों के होते हुए भी।